वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) गुजरात में कोई अपरिष्कृत कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Scheme to compensate the Employees of closed Textile Mills By BIFR

2704. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there is any scheme to compensate the employees of closed textile mills by BIFR; and

(b) if so, the details thereof; and by when it is likely to be implemented?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) to (b) Government has set up a Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme (TWRFS) to provide interim relief to the workers rendered jobless due to permanent closure of textile mills. The scheme came into force with effect from 15.09.1986. The scheme is also extended to partially closed units, provided the State Government recommend that the entire uneconomic activity (like weaving & processing) has been scrapped as a part of a rehabilitation package for sick/ weak mills (as per RBI definition) approved by the Nodal Agency/BIFR, provided the scrapped capacity is surrrendered for cancellation and endorsement is made on the licence/ registration certificate to that effect.

देश में कपास उत्पादन

2705. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 के दौरान देश में कपास के उत्पादन की मात्रा का अनुमान लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कपास की मांग की मात्रा का कोई आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक मांग किस दर से बढ़ी है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1995-96 (सित०-अगस्त) के दौरान देश में कपास का उत्पादन कपास सलाहकार बोर्ड (कैब) के 24.2.97 के अनुमान के अनुसार 160 लाख गांठों का था।

(ग) जी हां।

(घ) कपास सलाहकार बोर्ड के मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1995-96 के लिए देश में कपास के लिए मांग 159.00 लाख गांठों की थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक मांगों में वृद्धि की दर का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। राज्य सभा में देश में कपास उत्पादन के बारे में श्री राम जेठमलानी द्वारा दिनांक 19.3.1997 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2705 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

(आंकड़े लाख गांठ में — प्रत्येक गांठ 170 कि० ग्रा०)

वर्ष	खपत	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1993-94	127.00	1.59
1994-95	135.04	6.33
1995-96 (सितम्बर-अगस्त)	151.00	11.85

Bachawat Tribunal Award

2706. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI K.M. KHAN:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the height of the Almatti Dam has been increased violating the Bachawat Tribunal Award;

(b) whether the Centre would implement the recommendations of the Chief Minister's Committee appointed to look into the violations of the Award; and

(c) the measures proposed to put a halt to the height of the Dam and stop construction of the crest gate?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c) Bachawat Tribunal Award has not specified the height of Almatti Dam. Centre would have no objection to any consensus decision arrived at without violating the Tribunal Award.

Declaring Dumariaganj As Flood Affected Area in Uttar Pradesh

2707. SHRI RAM NATH KOVIND:
DR. RANBIR SINGH:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to declare Dumariaganj in Siddharthanagar district of Uttar Pradesh as a flood affected area;

(b) if so, the details thereof?

(c) whether any action has since been taken on these requests; and

(d) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

Allocation of Fund for the Accelerated Irrigation Benefits Programme

2708. SHRI P. SOUNDARAJAN:
SHRI O.S. MANIAN:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is fact that Rs. 27.70 crores has been allocated for the Accelerated Irrigation Benefits Programme for five States;

(b) if so, whether Tamil Nadu has been provided with such funds; and

(c) if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c) An amount of Rs. 818.50 crores has been approved as Central Loan Assistance (C.L.A.) under the Accelerated Irrigation Benefit Programme (A.I.B.P) during 1996-97 for 52 projects of 18 States out of which an amount of Rs. 40.00 crores has been allocated to Tamil Nadu.

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना

2709. **श्री अजीत जोगी:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) वृहद परियोजनाओं के लिए 10 वर्षों तथा मध्यम परियोजनाओं के लिए 5 वर्षों की सामान्य कार्यान्वयन अवधि मानते हुए मध्य प्रदेश में 22 वृहद एवं 34 मध्यम परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। इन परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत और नवीनतम अनुमानित लागत सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)। परियोजनाओं के पूरे होने में कोषों की कमी, भूमि अधिग्रहण, परियोजना के कारण बेदखल हुए लोगों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, वन एवं पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति, अपर्याप्त अन्वेषण और परियोजनाओं की सीमा में परिवर्तन के कारण विलंब होता है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत तीन चल रही परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 86.00 करोड़ रुपए की धनराशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में अनुमोदित की है।